Unorganized farm labourers

†*627. SHRIMATI VANGA GEETHA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state the action taken to protect interests of the unorganized farm labourers?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SHARAD YADAV): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

To protect the interests of workers including unorganized agricultural workers, the Government has enacted the Minimum Wages Act, 1948, the Equal Remuneration Act, 1976, the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 and the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. A social security scheme namely, 'Krishi Shramik^Samajik Suraksha Yojana-2000' has also been launched in selected 50 districts in the country with the objective of covering 10 lakh agricultural workers over a period of three years. The scheme envisages to provide through Life Insurance Corporation of India, life-cum-accident insurance, money-back, pension and superannuation benefits. Jan Shri Bima Yojana is also in operation for those below the poverty line or marginally above the poverty line which *inter-alia* includes agricultural labourers. Some other schemes for the welfare of rural workers including agricultural workers are Pradhan Mantri Gramodaya Yojana Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY), Employment Assurance Scheme (EAS), National Social Assistance Programme (NSAP) etc.

SHRI K. KALAVENKATA RAO: Sir, part (a) of my first supplementary is, whether the Government is considering rationalisation of the labour laws for ensuring a minimum level of protection of the workers, especially those who are working in the unorganized sector; if so, trie details thereof. Part (b) is, whether the Government proposes to set up an independent regulatory authority

†Starred question Nos. 621, 623 and 627 were taken together.

for unskilled labourers and provide them training in various skills, to improve their socio-economic status, and also to ensure social security to the workers in the unorganised sector.

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे है, वह मध्य प्रदेश से संबंध रखता है । इस सदन में इस पर घंटो बहस हुई है और जो बातें आपने कही है, उन सब बातो का मै जवाब दे चुका हूं लेकिन जो प्रश्न अब आप पूछ रहे है, यह मध्य प्रदेश से संबंध रखता है मध्य प्रदेश में इंस्टीटयूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की एक संस्था है जहां एक टास्क फोर्स श्रीमती झाबावाला की अध्यक्षता में बन हुआ है । उसे मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे है, उसका उत्तर इस प्रश्न के दायरे में नही आता है ।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, it is not relating to Madhya Pradesh alone. The workshop was held there, but that relates to the entire country. We cannot confine it only to Madhya Pradesh.

SHRI K. KALAVENKATA RAO: This workshop was on "The Unorganised Sector". It is related to the main question. Sir, my second supplementary is, whether the Government proposes to formulate a national policy to provide health facilities and environmental safety to the workers in the unorganised sector as a welfare measure; if so, the steps initiated in this regard.

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है और वह श्रीमती झाबावाला की अध्यक्षता मे काम कर रहा है । **…(व्यवधान)** ...

SHRI K. KALAVENKATA RAO: This question does not relate to the workers of Madhya Pradesh alone. It relates to the workers of the entire country.

SHRI SURESH PACHOURI: The Minister is from Madhya Pradesh, that is why he is giving stress to Madhya Pradesh.

SHRI SANJAY NIRUPAM: But he is not the Labour Minister of Madhya Pradesh. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव : सभापति जी, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए । मै जो बात कर रहां हूं वह इस क्वेश्चन के दायरे मे कह रहा हूं, इस सदन में दस घंटे इस पर बहस हुई है । यदि इससे संबंधित सवाल होता तो मैं जवाब देता । फिर भी जो प्रश्न इन्होने पूछा है, उसका

जवाब मै दे रहा हूं कि वहां एक टास्क फोर्स बना है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। उसकी एक वर्कशाप हुई जिसका उदघाट्न पी.के. अलग साहब ने किया और समापन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने किया। उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नही आई है। हमने इस संबंध मे मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है। माननीय सदस्य जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के बारे मे पूछ रहे है, वह निश्चित तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस संबंध मे जो भारत सरकार है, हमारा मंत्रालय है, वह अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को किस प्रकार सोशल प्रोटेक्शन दें, इस पर विस्तार से इस सदन में चर्चा हो चुकी है, हमारा मंत्रालय इस संबंध में पांच-छः मीटिंग्ज कर चुका है और इसका प्रश्न जब आएगा तो मै उसका विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां जो सवाल पूछा गया है, वह सिर्फ मध्य प्रदेश में जो टास्क फोर्स बनी है, उस पर जो वर्कशाप हुई है, उसकी रिपोर्ट अभी तक सुबाई सरकार को नही मिली है। जब सुबाई सरकार को रिपोर्ट मिलेगी तब इस मामले में देश में जहां भी नेशनल कंसेसस बनेगा, उस पर विचार करने का काम होगा अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के मामले मे खासकर पिछले पचास वर्षो मे कई मीटिंग हुई हैं लेबर कांफ्रेसस हुई है, आपके लेबर सेक्रेट्री भी बुलाए गए लेकिन इस मामले पर आम राय सूबो में नही बन पा रही है, स्टेट लेबर गवर्नमेंट के बीच नही बन पा रही है। निश्चित रूप से यह सवाल देश के सबसे लाचार और बेबस लोगो से वास्ता रखता है। इस मामले में कैसे कानून द्वारा उनकी रक्षा की जाए। नेशनल कंसेसस कैसे बने, इस मामले पर बहुत सालों से बहुत बहसे और जिरहें चली है। इस संबंध में सन 75 में और ज्यादा प्रयास हुए लेकिन सुबाई सरकारे इस मामले में एकमत नही है। सरकार अपने प्रयास में लगी हुई है। मैं आपसे और माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इस मामले में जब से श्रम मंत्रालय मेरे पास आया है तब से मै अकेले इसी काम में लगा हुआ हूं। जिसमे इसी काम में चौबीस घंटे लगा रहता हूं कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए। पूरे अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर मे , जैसे सोशल सिक्योरिटी है, उन्हे जो सुविधाएं मिली है, चाहे विदेश के मामले में हो या किसी और मामले मे हो वह ज़मीन पर एक नही है, और इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नही है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सवाल मध्य प्रदेश सरकार से वास्ता रखता है और मध्य प्रदेश सरकार के पास अभी तक जो टास्क फोर्स बनी है, उसकी रिपोर्ट नही आई है और न ही उस पर कोई विचार हुआ है।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, according to the reply given by the hon. Minister, the Krishi Shramik Samajik Yojana, 2001, has been launched in selected 50 districts in the country, with an objective of covering 10 lakh agricultural workers over a period of three years. Andhra Pradesh is also covered by the Scheme. I would like to know how many people are benefited under this Scheme.

श्री शरद यादव . सभापति जी, साधारणतया श्रम सुरक्षा योजना में तकरीबन एक लाख लोग हिन्दुस्तान भर के पचास डिस्ट्रिक्ट में है और पचास डिस्ट्रिक्ट के पचास ब्लाक्स में है । अभी तक इसमें एक लाख वर्कर्स एनरोल कर लिए गए है । यह एक अच्छी स्कीम है और हिन्दुस्तान का जो अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल लेबर है उसके लिए इस स्कीम से एक छोटा-सा ठोस कदम उठा है । इसके नतीजे उत्साहवर्ध्दक आ रहे है । आंध्र प्रदेश के विषय में मुझे मालूम नही है कि कौन से डिस्ट्रिक मे है लेकिन मे माननीय सदस्या को बता दूंगा कि यह कौन-से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन-से ब्लाक में है ।

MISS MABEL REBELLO: Question No. 623.

श्री शरद यादव . एम्प्लोएमेंट के बारे में जो सवाल पूछा गया है, इसमें पिछले तीन साल में ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर मे 0.5 परसेंट, लगभग डेढ़ लाख लोगो के रोजगार घटे है और अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में 0.98 रोजगार बढ़े है । निश्चित तौर पर इसके बारे में सरकार ने , गवर्नमेंट की इंप्लायमेंट जनरेशन जो स्ट्रेटजी है उसमे सेल्फ इंप्लयमेंट तथा वेज इंप्लायमेंट को बढ़ावा देना है । लेबर इन्टेंसिव सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इंप्लायमेंट जनरेशन करना है और स्किल्ड लेबर फोर्स को बढ़ावा देना है । यह हमारी स्ट्रेटेजी है । निश्चित तौर पर जो हमने कहा था एक करोड़ लोगो को जॉब देनी है, उसके बारे में हमारे मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयो से की तरह की योजनाए है, चाहे वे रोड की है चाहे वे कंस्ट्रक्शन की है । और कई तरह की योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है, विचार ही नही कर रही है बल्कि उनमे एलोकेशन हुआ है और निश्चित तौर पर जो हमने कहा था उस काम में उस बात में हम प्रयासरत है और निश्चित तौर पर अभी तक नही हो पाया है आगे के समय में इसमें नतीजे अच्छे आएंगे ।

MISS MABEL REBELLO: Sir, I had put my question in three parts, *i.e.* (a), (b) and (c). But the answer is totally incomplete.The Minister in his reply says, "The rate of growth of employment in the organised and unorganised sectors for major States and at the national level is given in the Annexure." But there was no Annexure. Just now I have got the Annexure. I wanted to have the statistics of three years. But the Minister has given the statistics for the years 1998, 1999 and 2000. The statistics for the year 2001 are missing. Then part (b) of my question has not been answered at all. In response to part (c) of my question he has given a general reply. He has not given a specific reply. In para 3 of his reply he says, "Particular attention would be paid to the policy environment influencing a wide range of economic activities which have a large employment potential." There is nothing specific. What are those economic activities which he has

mentioned? How is he planning to generate employment? In part (b) of my question, I specifically asked, "whether it is a fact that 50 lakh jobs have been lost in the organised and unorganised sectors?" These are authentic figures. In the organised sector, we have lost 4.5 lakh jobs by way of VRS, closing down of industries, etc. In the unorganised sector we have lost 45 lakh jobs. When this Government came to power, in their manifesto, the Government said that they would create one crore jobs annually. Instead of creating one crore jobs annually, they are losing 50 lakh jobs annually. What is the Minister saying? The answer given by the Minister is not at all satisfactory. I want complete answer from the Minister. When the question is in three parts, the answer should also be in three parts. He has given a general reply. He is not giving any specific reply, Sir, I want specific replies to my specific queries.

श्री शरद यादव : सभापति जी, जो सवाल "ए" है, "बी" है तो "बी" में जो सवाल पूछा गया है ....(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो : यहां कुछ भी नही दिया है। "ए, बी, सी" कहां है ?

श्री संघ प्रिय गौतम : जवाब देने दीजिए, जवाब सुन लें।

श्री शरद यादव : जो "बी" का है उसका भी जवाब मैने दिया है ...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो : मैं लाकर दे दूं आपको ? क्या यह "ए, बी, सी" है ?

श्री संघ प्रिय गौतम : जवाब तो सुन लें। कुछ कहने तो दें।

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मैने "बी" का भी जवाब दिया है कि जो हमारे पास आंकड़े है, या जो फिगर्स है, जो सर्वे है, उनमे 1.5 लाख जॉब्स कम हुए है। मैं आपके माध्यम से सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं कि यह फिगर ज्यादा हो सकता है, मै यह नही कह रहा हूं, लेकिन जो अवेलेबल है, जो सर्वे हुए है, उससे मैने उनको बताया है। निश्चित तौर पर जो जॉब क्रिएशन की बात है हम एक करोड़ जॉबस कैसे बनाएं ...(**व्यवधान**)....

कुमारी मैबल रिबैला . सर, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसका स्पेसिफिक रिप्लाई दीजिए।

श्री शरद यादव . स्पेसिफिक ही दे रहा हूं। I am answering specifically. सभापति जी, इंप्लायमेंट जनरेशन के बारे मे मैने कहा सरकार इस पर गंभीर है और सरकार यह मानती है कि आर्गेनइज्ड सेक्टर मे जॉबस कम हुए है। इसमे कोई शक नही है। आंकड़े की बात मै नही करता कि आंकड़े ....(**व्यवधान**).... हमारे ठीक है या आपके ठीक है ...(**व्यवधान**) ...

कुमारी मैबल रिबैलो : मैने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, उसका स्पेसिफिक रिप्लाई दीजिए। आप againजनरल बात कर रहे, सरकार गंभीर है। इसका क्या मतलब है ? मैने आंकड़े पूछे है । आप मुझे स्टेटिसटिक्स दे दीजिए । सब्सटैशएट कीजिए वह स्टेटिसटिक्स।

श्री शरद यादव : यानी एक लाख 50 हजार जॉब कम हुए । यह मैंने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया है .....**(व्यवधान)** ....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, the question was whether 50 lakh jobs have been lost in 2001-02 or not; the Minister is mentioning about 1999-2000. He should say whether the hon. Member is correct or not, Let him correct her, if she is wrong. इसका फिगर आपने दिया नही। मेरे ख्याल से, सभापति जी, इसके लिए झगड़ा नही करके, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर मंत्री जी चाहे तो वह फिर से आएं और अगले हफ्ते इसका जवाब ठीक तरह से लाये तथा इसके बारे में चर्चा करे और 2001-02 में 50 लाख जॉब्स लॉस्ट। It is a very serious charge, आपके मंत्रालय ने प्रश्न मिलने के बाद भी आपको यह रिप्लायी दिया । यह आपकी गलती नही है । आपके मंत्रालय ने सोचा ....**(व्यवधान)** . सर, इसमें कहा है ....**(व्यवधान)** .

श्री शरद यादव : सभापति जी, यह जो बात कह रहे है, यह ठीक नही है ....**(व्यवधान)** .

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Kindly go through the reply. Sir, Why should we put questions in (a), (b) and (c) parts, if the reply is going to be a general one?

श्री शरद यादव : यह जो बात कह रहे , यह ठीक नही है ....**(व्यवधान)** .

MR. CHAIRMAN: Let him speak ....*{Interruptions).*

श्री दीपांकर मुखर्जी : आप भी इंजीनियर है, हम भी इंजीनियर है ....**(व्यवधान)** .

श्री शरद यादव : मै तैयार ही हूं ...**(व्यवधान)** .

श्री दीपांकर मुखर्जी : आप चीफ मिनिस्टर रह चुके है, गौतम जी, आप मैंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप क्वश्चन का "सी" पार्ट देखिए और उत्तर भी देख लीजिए । ....**(व्यवधान)**.

श्री शरद यादव : माननीय सभापति जी, मैने कहा कि इस मामले में डिस्प्यूट है और जो भी आंकड़े मुझे मिले है मैं निश्चित तौर पर उनसे संतुष्ट नही हूं यानी हमारे हिसाब से जो आपने पिछले तीन साल का बोला है उसमें एक लाख पचास हजार हिसाब से जो आपने पिछले तीन साल का बोला है उसमे एक लाख पचास हजार ....**(व्यवधान)** .

श्री दीपांकर मुखर्जी : पिछले साल 50 लाख यानी 2001-02 मे 50 लाख जॉब समाप्त हुए है या नही , यह क्वश्चन है और यह बहुत सीरियस क्वश्चन है ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, यह सवाल मैने अपने मंत्रालय से पूछा है कि जो एक साल दिया गया है इसका भी मुझको बता दें और वह जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा । पिछले तीन साल का मै दे रहा हूं, लेकिन स्पेसेफिक सवाल जो पूछा है वह आंकड़े हमारे पास नही है, मै उनको आपके पास भेज दूंगा । **....(व्यवधान) .**

कुमारी मैबल रिबैलो : आप क्या कह रहे है **....(व्यवधान) .**

श्री दीपांकर मुखर्जी : बड़ा सीरियस क्वश्चन है ।

MR. CHAIRMAN: Let him reply ...*(Interruptions).* Please hear the Minister ...*(Interruptions).*

कुमारी मैबल रिबैलो : स्पेसेफिक क्वश्चन का स्पेसेफिक रिप्लायी देना होगा, आफ्टरआल रिप्लायी चाहिए ।

श्री संघ प्रिय गौतम : सर, दो-दो सदस्य एक साथ सवाल पूछ रहे है ।

MR. CHAIRMAN: Let him reply ....*(Interruptions).* Please hear the Minister ....*(Interruptions).*

श्री शरद यादव : सभापति जी, इस पर मैने आपके माध्यम से बता दिया है कि जो स्पेसेफिक "बी" पार्ट वाला सवाल है, इसके बारे में आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नही है । हम आंकड़े उपलब्ध करके आपको बताने का काम करेंगे । अब जो रोज़गार पैदा किए जा रहे है जो 2001-02 में रूरल डिवेलपमेंट में 8080 करोड़ रूपए अलाट किए गए है, प्रधान मंत्री संपूर्ण रोजगार योजना में 4989 करोड़ रूपए 2001-02 में अलाट किए गए, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 2375 करोड़ का प्रावधान किया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना में 815 करोड़ अलाट किए गए है, वेस्ट लैंड डिवेलपमेंट में 2000-01 में 900 करोड़ रूपए दिए गए है । यह जो नेशनल हाईवे डिवेलपमेंट प्रोग्राम है, उसमे 94 हजार करोड़ रूपये आने वाले 2007 तक खर्च करने है । इतना पैसा इसमे अलाट किया गया है । रोड लिंकिंग में 4000 करोड़ सन 2000 से लेकर 2007 तक खर्च किए जायेंगे, रोड सेफ़्टी पर 17 करोड़ खर्च किए जायेंगे , प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पर 1991-92 मे 293 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में 2002 से लेकर आगे आने वाले समय में 1250 करोड़ खर्च किए जायेंगे । और एम्प्लायमेंट जनरेशन प्रोग्राम पर के.वी.आई.सी. के अंतर्गत 2001-02 में 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । सभापति जी, सरकार ने ये सारा एलोकेशन इन मदो पर किया है । अब चाहे वह रोड कंस्ट्रक्शन हो

या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, ये सारे प्रोग्राम प्रधान मंत्री सड़क रोजगार योजना के अंतर्गत आते है और ये खासकर रोजगार को पैदा करने वाले और बढ़ाने वाले प्रोग्राम है । यह सरकार की योजना है जिसे मैने मोटे-मोटे तौर पर आप के सामने रखा है ।

MR. CHAIRMAN: Mr. B.P. Singhal.

MISS MABEL REBELLO: Sir, I want to...

MR. CHAIRMAN: No. no. When the questions are clubbed together, only the first supplementary is allowed.

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, I have never been able to comprehend how the figures pertaining to the unorganised sector are calculated and published very authentically in various magazines and other publications. For instance, take the case of migrant labour, the labour that does work at brick kilns, which are seasonal, or the sugarance labour. How do you calculate them? Or how are they calculated. If all this calculation is being done through the Employment Exchange, then I want to put a question to the hon. Minister. There are thousands of Employment Exchanges; every district has an Employment Exchange. Has the Labour Ministry computerised them all, because I know of a case where one person is registered in, at least, half-a-dozen Employment Exchanges? So, if all the common names are removed from the Employment Exchanges, perhaps, we may get a more accurate figure. Has any exercise been undertaken to remove the common names from the Employment Exchanges all over the country? And, what is the methodology of calculation?

श्री शरद यादव : सभापति जी, इस के लिए एक ही जरिया है और वह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज जोकि सूबाई सरकारों के हाथों में है । हम इस के आंकड़े उन से ही कलेक्ट करते है और वहां आंकड़े हम जवाब मे देते है । अब जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इन मे बहुत से कॉमन नेम्स भी होते है, जिन्हे छांटने का काम मुशिकल होता है । दरअसल हम तो एन.एस.एस.ओ.आई. द्वारा किए गए सर्वे के आंकडे देते है ।

SHRI CHO. S. RAMASWAMY: When we speak of the unorganised sector, I think we also speak of many self-employed persons working on the streets and platforms. They have either small eateries or they do ironing of clothes or they have teashops. They sell so many sundry items like toys and other things. In the names of cleaning the cities, in the name of hygiene, many Governments

are doing away with these self-employed persons. This is a huge problem in every city because all those persons are removed from the platforms, both on the ground of ageing and for purposes of smooth traffic. Should not the Government have some scheme, some plan, to reconcile the two interests, one, of an honest livelihood for these persons who do not break the law and, on the other, of hygiene, traffic and needs of modern living. Unless a scheme is drawn to reconcile these two interests, we will be converting all these honest persons into anti-social elements and petty thieves. Has the Government got any scheme to get these two interests reconciled?

श्री शरद यादव : सर, माननीय सदस्य की जो कनसर्न है, उस के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति और सहमति है । सभापति जी , निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान में है जिस में एक बड़ी संख्या रेहड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले, तांगे वाले, छोटी दुकान चलाने वाले और मूंगफली बेचने वालों की आती है और शहरो मे इन को बड़े पैमाने पर हटाया जाता है । लेकिन सवाल सीधा सूबाई सरकार से जुड़ा होता है, केन्द्रीय सरकार के हाथ मे यह काम नही है । निश्चित तौर पर माननीय सदस्य अलग-अलग सूबो से आते है और वहां भी इस तरह के रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले, तांगे वाले और दूसरे अन-अर्गनाइज्ड वर्कर्स है, लेकिन इन सब के लिए तमिलनाडु कर्नाट्क और केरल की सरकारे, एग्रीक्लचर के क्षेत्र में बंगाल की सरकार अच्छे काम कर रही है और इनके लिए अच्छे लेजिस्लेशन भी ला रहे है, लेकिन उनके सामने भी दिक्कत आ रही है । यह जो सवाल है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, एक बड़ी समस्या है । हिन्दुस्तान में जो भी बेरोजगार होता है वह या तो पान का पटरा लगाने लगता है या कहीं मोची का काम करने लगता है । मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूं कि इस मामले पर पूरे देश भर में एक कंसेंसस बनकर सामने आए कि कैसे इनको प्रोटेक्शन दिया जाए , कैसे इनको ठीक किया जाए । कंस्ट्रक्शन लेबर के बारे में अभी दोनो सदनो में एक कानून पास किया गया । मैने सूबाई सरकरो और सबसे कहा, मगर एक दो सूबाई सरकारो ने इंपलीमेंट किया, बाकी सरकरो ने नही किया । ये केस्ट्रक्शन वर्कर भी ऎसे ही लोगो में आते है । तो यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर जो मननीय सदस्य ने कहा, मै मानता हूं की काफी बड़ी दिक्कत है, जो अच्छे लोग है वह ईमानदारी से अपनी रोजि रोटी कमाना चाहते है, किन्तु हिन्दुस्तान में आबादी बढ़ने से, शहरो क विस्तार होने से गांवो में रोजगार के अवसर कम होने से बड़े पैमाने पर लोग गांवो से उजड़ कर शहरो में आते है वहां लोग किसी तरह से बाजारो में सड़क के किनारे अपनी रेहड़ी लगाकर काम करते है या एक तरफ बैठक जूते सुधारने का काम करते है यह कई तरह की मशीने सुधारने का काम करते है या फिर साइकल की पंचर

बनाने का काम करते है । अब इनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे इनको प्रोटेक्शन दी जाए, यह एक बड़ा सवाल है ।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं एक तो इनका जवाब तर्कसंगत नही है, एक तरफ तो आप कहते है कि संगठित क्षेत्र में एक लाख पचास हजार रोजगार के अवसर घटे है और असंगठित क्षेत्र की जो इन्होने बात कही कि वह तांगेवाला, रिक्शे वाले, मोटर वाले या जिनकी बात कही, मै सोचता हूं कि इस प्रश्न का उसमे कोई संबंध नही है । मैं स्पेसिफिक उनसे पूछना चाहता हूं, यह पार्ट 'सी' में जो है— the manner in which the Government propose to address the problem of educated unemployed, अगर माननीय मंत्री जी का जवाब देखे तो उसके जवाब में उन्होने कहा है – अत्याधिक रोजगार संभावना वाली आर्थिक गतिविधियो की एक विस्तृत श्रंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष बल दिया जाएगा । तो जो देश में बेरोजगार है उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए यह माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है , मै सोचता हूं कि मंत्री जी पूरी तैयारी से नही आए है और दूसरा जिस प्रकार का इन्होने जवाब दिया है , दसवी योजना के बारे में जो उल्लेख किया है, मै चाहूंगा, सभापति जी, कि इस प्रश्न पर सही ढ़ंग से स्पष्ट उत्तर आने के लिए इसे किसी दूसरे दिन के लिए रखा जाए ताकि मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ सदन मे आएं और सदन को सही जानकारी देने की कृपा करें ।

श्री शरद यदव : सभापति जी, मै वोरा जी को बताना चाहूंगा कि जब इस सदन मे लेबर मिनिस्टरी पर डिबेट चली थी तो एक लंबी डिबेट चली थी, विस्तार से डिबेट चली थी । माननीय सदस्य ने जो पूछा था, निश्चित तौर पर मै उस पर बोल रहा था ।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय सभापति जी, प्रश्न संख्या 623 भी इसके साथ लिया जा रहा है ।

श्री शरद यादव : मै कहां एतराज कर रहा हूं ।

श्री मोती लाल वोरा **:** माननीय सभापति जी, प्रश्न संख्या 623 के पार्ट सी के बारे में मैंनें पूछा है ।

श्री शरद यादव : माननीय सभापति जी, अगर वोरा जी मेरी बात सुन लेंगे तो जरूर उनकी समझ मे आ जाएगा । मेरी विनती यह है कि जो सवाल यहां पूछा जा रहा था । जो माननीय सदस्य रामास्वामी जी ने पूछा था, उसके बारे में मै बोल रहा था । उन्होने एक ऐसा सवाल उठाया था कि हिन्दुस्तान के गांवो से उजड़ कर बेरोजगार होकर लोग बड़े पैमाने पर शहरो में आ रहे है और वह लोग शहरो में आकर रोजगार के लिए रास्तो पर, किनारो पर

बैठते है, उस सवाल का इस से वास्ता नही है, तब भी मैने उन का जवाब देने का काम किया कि इस संबंध मे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारे अच्छा काम कर रही है । जो अपने पार्ट 'सी' के मामलें मे सवाल पूछा है, तो इस मामले मे एक अहलुवालिया कमेटी बनी थी, उसने जो रिकमंडेशन दी थी, उन पर विवाद हो गया है और अब प्लानिंग कमीशन ने एक एस.डी. गुप्ता कमेटी बनाई है इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेस यही है कि कैसे एंपलायमेंट जनरेट किया जाए , उस कमेटी ने जितनी रिकमंडेशन दी थी, वह सारी रिकमंडेशन एस.डी.गुप्ता कमेटी को दे दी गई है । कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, कैसे जो एंपलायमेंट का फिगर गिर रहा है उसको रोका जाए, आर्गेनाइज्ड सैक्टर है और अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इसके बावत हमारे जो लेबर सेक्रेटरी है उनकी चेयरमेनशिप में भी एक कमेटी बनी है । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सब्मिट कर दी है और निश्चित तौर पर उसका प्रपोजल आने वाला है । हिन्दुस्तान मे जो अनएम्लायमेंट है, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे पास आई.टी.आई. बहुत कम है । पूरे देश भर मे आई.टी.आई. के बारे मे अगर मै बताना चाहूं तो हमारे पास 75 तो सैंट्रल इंस्टिट्यूट है, 4500 के करीब आई.टी.आई. प्राइवेट सैक्टर में है या उन्हे स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और हिन्दुस्तान में स्किल लेबर दुनियाभर में सबसे कम है । हमारी कोशिश है कि आई.टी.आई. का विस्तार किया जाए । बहुत से लोग आई.टी.आई. नही जाते हैं, अपने तरीके से अपना काम सीख लेते है मिस्त्रीगिरी का काम सीख लेते है, और कोई स्किल्ड वर्क सीख लेते है, मशीन सुधारने का काम सीख लेते हैं । तो जो स्किल उन्होंने हासिल किया है,उसके आधार पर बाजार में उनको किसी तरह से अवसर मिल सके, ऐसा प्रयास भी हमारा चल रहा हाय और आने वाले समय में इसके लिए एक बड़ा पैसा ऐलोकेट करने के लिए प्लनिंग कमीशन से हमने आग्रह किया है । इस तरह से सरकार प्रयास कर रही है ताकि जो अनएम्पलयड यूथ है, चाहे वह शिक्षित है या अशिक्षित है, उसको काम मिल सके ।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह : महोदय, प्रश्न संख्या 623 के तीसरे भाग में कहा गया है, "the manner in which Government propose to address the problem of educated unemployed," इस बारें मे मंत्री जी का जवाब भी है और आकलन दिया गया है किस विभाग में समस्या का निदान कैसे हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि जवाब पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो मै सरकार से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जानना चाहता हूं कि इस जाईर्गेटिक प्राब्लम को सॉलव करने के लिए जो सरकारी रास्ते बनाए गए है, सरकार क्या उन्ही पर कार्य करेगी या सेल्फ एम्प्लायमेंट पर भी जोर दिया जाएगा? मेरे विचार मे सेल्फ एम्पलॉयमेंट पर ज्यादा जोर देने से इसका निदान हो सकता है । इसके साथ ही साथ मै कहना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या राज्य सरकारो की, उसके विभिन्न विभागो या संस्थाओ की कोई बैठक बुलाई जाएगि ? श्रम मंत्रियो की

बैठक होती रहती है, श्रम सचिवो की भि बैठक होती रहती है, मै जानना चाहता हूं कि इस समस्या से निबट्ने के लिए क्यां सरकार के विभिन्न विभागो से य सरकारी संस्थाओ से मिल-जुलकर कोई उपाय किया जाएगा क्योंकि जिस ढ़ंग का प्राब्लम पैदा हो रहा है उसमे अनआरगेनाइज्ड सैक्टर और आरगेनाइज्ड सैक्टर में इतनी क्षमता नही हो सकती कि वह इस वास्ट अनएम्प्लायमेंट का सामना कर सके ? इसलिए मै मंत्री जी से यह स्पेसिफिक जानना चाहूंगा की क्या सरकार की यह इंर्टेशन है या सरकार की ऐसी योजना है कि सेल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम को बड़े पैमाने पर जनरेट करके वह इस जाइगेंटिक प्राब्लम का मुकाबला कर सके ?

श्री शरद यादव : सभापति जी, माननीय सदस्य ने सही कहा है, सरकार सबसे ज्यादा प्रयास कर रही है कि सेल्फ एम्प्लायमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट किया जाए और इस मामले में सरकार चिंतित भी है, प्रयासरत भी है । आज ही शाम पूरे देश से लेबर मिनिस्टर और लेबर सैक्रेटरीज़ मैने बुलाए है, और कल उनके साथ मेरी मीटिंग है और इन सारें सवालों पर, जो माननीय सदस्य पूछ रहे है, जो बड़े कठिन सवाल है और कठिन प्रयासो से ही इनका समाधान हो सकता है, विचार किया जाएगा । यह प्रयास तभी सफल हो सकता है जब सूबई सरकारों की भी इस पर सहमति हो जाए ।

श्री मोती लाल वोरा : मेरा कहना है कि जो राज्यो के जो श्रम मंत्री है, आप उनकी इसी सत्र के दौरान एक बैठक बुला ले ताकि आपको सही ढ़ंग से तथा पूरी जानकारी मिल सके और राज्यो मे क्या हो रहा है, उसका भी आपको पता चल सके । इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्यो के श्रम मंत्रियो की एक बैठक आप शीघ्रातिशीघ्र बुलाएं ताकि हर राज्य को स्थिति की जानकारी अपको हो सके ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, मैने अभी कहा कि कल ही मैंने बैठक बुलाई है, वोरा जी को शायद पता नही है या यह सुन नही सके, मैने कल ही बैठक बुलाई है और यह मीटिंग इस देश में पिछले 50 सालों से लगातार चल रही है । हमारे ज़माने में ...(**व्यवधान**) ....

श्री मोतीलाल वोरा : आप बहुत विद्वान आदमी है, श्रम नीति के बारे में आपको पूरी जानकारी है और आप काफ़ी अनुभवी है । माननीय प्रधान मंत्री ने लाल किले से जो घोषणा की थी हम एक करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर देंगे, मै जानना चाहता हूं कि उन एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की घोषणा का क्या हुआ ?

श्री शरद यादव : वोरा जी, मैने इसके बारे मे बताया है । निश्चित तौर पर हमें सैल्फ इम्प्लायमेंट तथा वेज इम्प्लायमेट को बढ़ावा देना है । यह विचाराधीन है और हम इस पर काम कर रहे है ।

DR. T. SUBBARAMI REDDI: Mr. Chairman, Sir, I would Hke to point out that there has been a slowdown in the employment in the public sector. It was 1.52 per cent per annum in the years between 1983 and 1994. But now a negative growth which started between 1994 and 2000, has gone to .03 per cent. So, I would like to know from the hon. Minister how this negative growth has started. This is part one of my question. The second part is, as just now we have heard, the hon. Prime Minister had promised in 2000 in his Independence Day Speech on 15th August that one crore jobs would be created. In his speech next year, he did not at all touch this point. Sir, part (c) of the main question about the manner in which the Government proposes to address the problem of educated unemployment has not been answered. The answer has not come so far. हम सोचेंगे , हम इस पर काम कर रहे है, that is not correct. I would like to know from the hon. Minister what has been the progress till today—not a meeting today or tomorrow. Secondly, there are so many schemes funded by the Central Government to create self-employment. I would like to know what efforts have been made to create self-employment's immediately, through the funds available under the Central Government's Self-employment Scheme. What steps have been taken by the Government to solve the problem of educated unemployment? As you know, there is a lot of frustration among the educated youth because there is no job for them. As a result, they are going on a wrong track. This is the most burning problem of the country. मीटिंग्ज़ करने से कुछ नही होता है । Therefore, I would like to have a categorical assurance from the Hon. Minister to this House as to how they are going to solve this problem and in what way they are going to make progress in this regard .....(*Interruptions)*....

श्री शरद यादव : सभापति जी, मै इन बातो का जवाब दे चुका हूं । यह जो एक करोड़ लोगो को रोज़गार देने का सवाल है, इसके बारे में मैने बताया है कि कहां-कहां कितनी-कितनी धनराशि का ऐलोकेशन किया गया है । प्रधान मंत्री जी ने जो एक करोड़ लोगो के लिए रोज़गार के सृजन की बात कही है, इस धनराशि से आने वाले समय में उससे अधिक रोज़गार का सृजन होगा । महोदय, शिक्षित बेरोजगार युवकों के बारे में मैने कहा कि जो शिक्षित बेरोजगार युवक है, उन्हे रोजगार देने के लिए शिक्षा की योजना को इस तरह बनाना पड़ेगा कि बड़े पैमाने पर स्किल्ड लेबर तैयार हो सके । इसके बारे में मैंने सदन को बताया है । आगे की योजना के लिए एस.पी.गुप्ता ...(**व्यवधान**) ....

सभापति महोदय, यह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है । जब मैंने साफ-साफ आंकड़े देकर बताया है कि रोजगार कैसे पैदा होगा, मैने धनराशि का ऐलोकेशन भी बताया है, उसके बाद भी माननीय सदस्या बार-बार खड़ी हो रही है **... (व्यवधान)**

कुमारी मैबल रिबैलो : आपने क्वश्चन का कोई स्पैसिफिक जवाब नही दिया है **....(व्यवधान)**

श्री सभापति : हो गया **....(व्यवधान)**

श्रीमति सरोज दुबे : सभापति महोदय, मै माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में सबसे ज्यादा रोजगार का नुकसान महिलाओ का हो रहा है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अकुशल है । जब तक मशीनीकरण नही हुआ था, तब तक उनको काम मिल जाता है और वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकने में समर्थ थी । मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस उदारीकरण के कारण जो शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं बेरोजगार हो रही है उनके हित के लिए, उन्हे रोजगार देने के लिए आप वैश्वीकरण के कौन से कदम उठाने जा रहे है ? इन बेरोजगार महिलाओं की समसयाओं को दूर करने के लिए आप क्या करने जा रहे है ।

श्री शरद यादव : महोदय, जो पहला सवाल था, उसमे मध्य प्रदेश में जो टास्क फोर्स बना है, उसके बारे में पूछा गया था । जो ग्लोबलाइजेशन की नयी रेजीम आई है, उसके चलते हमारे मंत्रालय पर इसका कितना असर होने वाला है, इसकी एक स्ट्डी चल रही है । सेकेंड लेबर कमीशन हमने बनाया हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी जल्दी ही आने वाली है। सरोज जी ने जो बात पूछी है, उस रिपोर्ट से पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन की रेजीम के चलते महिलाओ के रोजगर पर और अन्य मजदूरों के रोजगार पर कितना असर पड़ेगा ।

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, the hon. Minister has mentioned in his reply that particular attention would be paid to the policy environment influencing a wide range of economic activities which have a large employment potential. So, I would like to know from the hon. Minister whether—after the report of the 21st Workshop on Unorganised Labour Sector—there is any proposal to formulate a scheme for payment of Provident Fund; and whether there is any insurance scheme for all types of unorganised workers who constitute 90 per cent of the workers in the country.

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, जो पहला सवाल था उसमे माननीय सदस्या जो पूछ रही है, वह टर्म्स आफ रिफ्रेंस में नही है । उसके टर्म्स आफ रिफ्रेंस में, एग्रीकल्चर मे, फॉरेस्ट में, शहरो में, अन्य सैक्टरो मे जो उनके लिए वेलफेयर फंड बनाए गए है तथा जो एक्सिटिंग वेलफेयर फंड है, उनको डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर बोर्ड बनाकर के उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए , मिनिमम वेजिज पर कैसे प्रोगाम को बढ़ाया जाए, स्किल्ड अपग्रेडेशन कैसे किया जाए , माईग्रेंट लेबर के लिए क्या सुविधाएं दी जाए ग्लोब्लाइजेशन को देखते हुए क्या उसमे होने वाला है । यह मध्य प्रदेश की योजना है और वहां की टास्क फोर्स को यह काम दिया गया है ।

SHRI MURLI DEORA: Sir, when the NDA came to power, they had made a programe, the National Agenda for Governance. Under the National Agenda for Governance, the main theme of the agenda was 'बेरोजगारी हटाओ'eradicate unemployment'. During the last two years, more than two million jobs have been lost, instead of giving 10 million jobs every year. Several hundreds and thousands of small-scale, medium-scale and public sector industries have been closed. I would like to know what has happened to the National Renewal Fund, which was created earlier. How much money, how much resources have been provided to the National Renewal Fund by the Government? How much of that has been disbursed? What is the future programme of the National Renewal Fund?

श्री शरद यादव : सभापति जी, इस सवाल में यह आता नही है । मै इसका उत्तर माननीय सदस्य को भेज दूंगा ।

प्रो. रामगोपाल यादव : श्रीमन , आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे सवाल पूछने की इजाजत दी । माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में पहले बहुत मीटिंग हुई थी । अब भी आपका जमाना है और कल भी आपका जमाना है और कल भी मीटिंग करने जा रहे है । आप जितने सवालो का जवाब दे रहे है, स्पेसिफिक सवाल का जनरल जवाब दे रहे है। मै अपने जनरल सवाल का स्पेसिफिक जवाब चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, आप मेरा सवाल नही सुन रहे है, कुछ पढ़ रहे है

मै बेसिकली अध्यापक हूं और जब पर्चा आ गया तो उससे हटकर पूछूंगा । मेरा सवाल यह है कल जो मीटिंग आप करने जा रहे है, उस मीटिंग में आपकी क्या योजना है, कैसे लोगो को रोजगार देने का काम करेंगे ? क्या इसकी कोई स्पेसिफिक संख्या है कि इस वर्ष के अंत में इतने बेरोजगार लोगो को रोजगार देंगे ? माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो

एक करोड़ की घोषणा की थी, वह तो आप नही बता पाए कि कितने लोगो को रोजगार दे पाए। फिर भी अगर आपके पास जानकारी हो कि कितने लोगो को रोजगार मिला है उसकी संख्या बताएं ? जो कल योजना बनाने जा रहे है उसमे कितने लोगो को रोजगार देंगे ?

श्री शरद यादव : रामगोपाल जी ने मेरी बात ठीक से सुना है जो मैने जवाब दिया है। यानि हिन्दुस्तान मे जो शिक्षित बेरोजगार है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है शिक्षित और गैर शिक्षित लोगो में यह समस्या कम है। एक तो हमारी योजना यह है कि स्किल्ड वर्कर्स को कैसे और बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए। हमने 10 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रपोज किया है कि 4700 करोड़ रूपये ऐलोकेट किये जाएं। निश्चित तौर पर आपने अनऑरग्नाइज्ड लेबर के बारे में जो कहा है- शिक्षित के बारे में लोगो ने पूछा, अब मै अनऑरग्नाइज्ड सैक्टर के बारे में बता रहा हूं कि इस पर मैने ऐलोकेट करके, नम्बर के साथ, बजट ऐलोकेशन बताया कि जब रोड बनेगी, मकान बनेंगे ...

प्रो. रामगोपाल यादव : आपने पैसा ऐलोकेट किया है पर उसमे कितने लोगो को रोजगार मिलेगा ?

श्री शरद यादव : उस संबंध मे काम चल रहा है।

प्रो. रामगोपाल यादव : कितने लोगों को काम मिलेगा ?

श्री टी.एन.चतुर्वेदी : वह सूचना लेबर मिनिस्टर देंगे।

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, यह जो मैने ऐलोकेशन बताया, उस पर काम चल चुका है और लोगों को रोज़गार मिले हुए है। मैने कहा कि अनऑरग्नाइज्ड सैक्टर में जो रोजगार है, वह बढ़ा है, .98 परसेंट बढा है जबकि ऑरग्नाइज्ड सैक्टर में घटा है।

श्री नीलोत्पल बसु : आप कल्पना से बता रहे है।

श्री शरद यादव : सभापति जी, माननीय सदस्य जो कह रहे है, मै उनकी जनकारी को चैलेंज नही कर रहा हूं।

प्रो. रामगोपाल यादव : श्रीमन जो रोड्स वगैरह के बारे मे मंत्री जी बता रहे है, अब स्थिति यह हो गयी है —माननीय सड़क मंत्री जी बैठे हुए है — लोग मशीनो से काम कर रहे है और बड़ी-बड़ी मशीनें आ गयी है जिससे लोगों को रोजगार नही मिल रहा है। जहां सौ मजदूर काम करते थे, वहां एक मशीने 200 लोगों को बराबर काम कर रही है। इतने बड़े-बड़े व्हीकल्स और मशीने आ गयी है कि एक दो किलोमीटर रोड बनाने के लिए भी मशीने काम करती है और किसी को काम नही मिलता।

श्री शरद यादव : माननीय रामगोपाल जी, 30 करोड़ मैनडेज़ इस अकेले नेशनल हाईवे प्रोजैक्ट से लोगों को मिलेंगे और यह आकड़े मैं आपको – जब इसका जवाब दे रहा था, तब जवाब नही दिया था – दूसरा जवाब मै बता रहा हूं कि 30 करोड़ मैनडेज़ है । निश्चित तौर पर मैं आपकी बात मानता हूं कि ...

प्रो. रामगोपाल यादव : बड़ी-बड़ी मशीने आ रही है कहां मैनडेज़ मिल रहा है ?

श्री शरद यादव : सभापति जी, मै इनकी बात मानता हूं कि मशीनों के चलते रोजगार घटे है ।

श्री संजय निरूपम : मशीनें चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, my question is regarding the welfare schemes for the unorganised sector. There was a demand for bringing a comprehensive central legislation for the agricultural labour and we have during the last 20 years, held a number of discussions about this legislation. More than a dozen discussions between the State Labour Ministers, Labour Secretaries and the Central Government have already taken place during these two decades. But, so far, nothing fruitful has come out for the unorganized sector. The Government has announced only this Bima Programme, which also has failed in its implementation. You announced that one million agricultural labourers will be enrolled in this programme, but only a little more than five thousand labourers were enrolled. So, this programme has failed entirely. In such a situation, I would like to know whether the Government will come out with a comprehensive legislation for the agricultural labourers or not. And will the Government give an assurance in this House regarding the legislation? That is the first part of my question.

Sir, the second part of my supplementary is regarding the total mandays of employment, which is going down now-a-days. Does the Government have any idea regardingthe number of mandays available for the agricultural labourers in our country? Will you give an assurance in this House regarding the legislation? And, will you give the details regarding the number of mandays available in the country?

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात ऐग्रीकल्चर लेबर के बारे में कही, वह शत प्रतिशत सही है । इतनी बार मीटिंग्स हो चुकी, इतनी बार कॉम्फ्रेंसिंग हो चुकी लेकिन इस सवाल पर – हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जो लोग है, जिन्हे बिलो पॉवर्टी लाइन कहते है जिनकी सबसे ज्यादा खाने और रहने की दिक्कत है, उनके बारे में पिछले दो डिकेड्स में कई कॉन्फ्रेंसिंग हुई, सब लोग बैठे, प्राइम मिनिस्टर भी हर मीटिंग में रहे लेकिन इस सवाल को हम आज तक हल नही कर पाए है । सभापति महोदय, मै आपाके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह मामला सूबाई सरकारों के हाथ में है, और वे इस संबंध में सहमत नही होती, इस संबंध में जब भी लैजीस्लेशन बनाने का काम होता है- यह राज्यों की सभा है, आप लोग अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कोहिए, मैनडेट दीजिए कि ऐग्रीकल्चर लेबर के बारे में कानून बनाने के बारे में सहयोग दें । मैं सब सरकारों के बारे में नही कह रहा हूं लेकिन इसमें कांन्सैंसस नही बन पाता, आम सहमति नही बन पाती ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : आप हां बोल दीजिए ।

श्री शरद यादव : लेजीस्लेशन लाएंगे भी तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा ? वह सूबाई सरकारें ही तो करेंगी ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : लेजीस्लेशन लाइए, इम्प्लीमेंट कराने का काम हमारा है ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, बहुत से कानून है, बहुत सा पैसा दिया हुआ है लेकिन वह पूरा सूबाई सरकारों के हाथो में नही जाता है । **...(व्यवधान)...**

श्री दीपांकर मुखर्जी : आप लेजिस्लेशन तो लाइए ।

श्री शरद यादव : सभापति जी, देश में जो ई.एस.आई. हॉस्पिटल्स है, उनको केन्द्रीय सरकार इतना पैसा देती है लेकिन उनकी हालत क्या है ? कुछ सूबों में तो ठीक है लेकिन जिन्हे सूबाई सरकारे चला रही है, उनकी हालत क्या हालत क्या है? निश्चित तौर पर इसमें उनकी सहमति लेना जरूरी है । इसका इंप्लिमेंटेशन तभी हो सकता है जब सूबाई सरकारों को विश्वास में लिया जाए । यह राज्यो की सभा है और यहां राज्यो के लोग है, आप अपनी-अपनी राज्य सरकारों पर दबाव डाले और आम सहमति बने तभी यह हो सकता है ।

श्री दीपांकर मुखर्जी : आप लेजिस्लेशन लाइए, उसके बाद हो जाएगा ।